श्री मधु लिमये : मेरा भी यही व्यवस्था का प्रश्न था। जब बैंक आफ बड़ौदा के बारे में मैंने सूचना दी थी, तो आप को पता होगा, मंत्री महोदय ने जब कहा कि मैं नकारात्मक उत्तर देने जा रहा हूं मुझे कोई जानकारी नहीं है तो मेरे कहने पर उस को टाल दिया गया था और पूरी जानकारी जब आई तब लिया गया। इसी प्रकार से मैं माननीय विभूति मिश्र जी के सुझाव का समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जब पूरी सूचना आए तब इस को लिया जाय।

MR. SPEAKER: The points of order are quite valid. I think this should be postponed till tomorrow.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH): The Minister of Commerce is dealing with it. There has been some difficulty in communications also. We could not speak to him on the telephone early enough. I do not know if the report will be ready even by tomorrow. I will let the secretariat know if I get any information today.

MR. SPEAKER: If he gets the information today, it will be put down for tommorrow. Otherwise, it will be put down at a later date.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): You can allow one more notice under Rule 377.

MR. SPEAKER: It is a windfall for you? I will try.

12.02 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

REVIEW AND ANNUAL REPORT OF COCHIN REFINERIES LIMITED

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICARLS (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(1) Review by the Government on the working of the Cochin Refineries Limited, for the year ended 31st August. 1972.

(2) Annual Report of the Cochin Refineries Limited, for the year ended 31st August, 1972 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[*Placed in Library. See* No. LT-5896/73]

REPORTS UNDER MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI BEDABRATA BARUA): I beg to lay on the Table:—

(1) A copy each of the following Reports of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission under section 62 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969:—

(i) Report under section 21(3)(b) of the said Act in the case of M/s. Century Spinning and Manufacturing Company Limited, Bombay and the Order dated 1st June, 1972 of the Central Government thereon.

(ii) Report under section 21(3)(b) of the said Act in the case of M/s. Carborundum Universal Limited, Madras and the Order dated 1st October, 1971 of the Central Government thereon.

(iii) Report under section 21(3)(b) of the said Act in the case of M/s. Vidyut Metallics (Prop. Panama Private Limited) Calcutta and the Order dated 16th July, 1973 of the Central Government thereon.

(iv) Report under section 21(3)(b) of the said Act in the case of Systronics (a division of Sarabhai Sons Private Limited) Ahmedabad and the

[Shri Badanbrata Barua]

Order dated 20th July 1973 of the Central Government thereon.

(v) Report under section 22(3) (b) of the said Act in the case of M/s. T. V. Sundram Iyengar and Sons Private Limited, Madurai and the Order dated 2nd December 1972 of the Central Government thereon.

(vi) Report under section 21(3) (b) of the said Act in the case of M/s. Hindustan Aluminium Corporation Limited, Bombay and the Order dated 31st July, 1973 of the Central Government thereon.

(2) A statement (Hindi and English versions) explaining the reasons for not laying the Hindi version of the above Report and orders of Government thereon simultaneously

[*Placed in Library. See.* No. LT-5897/73]

12.04 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) ALLEGED REGISTRATION OF INDIAN COTTON MILLS FEDERATION UNDER INDIAN TRADE UNIONS ACT TO AVAIL EXEMPTION FROM INCOME-TAX.

श्री मधु लिमये बांका : अध्यक्ष महोदय मैं जो प्रश्न उठाना चाहता हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 11 के तहत चैरिटेबल परपज़ेज के लिये जो आमदनी होती है वह इनकम टैक्स के लिये मानी नहीं जाती है। उसे माफ किया जाता है और उसी के तहत भारत की ट्रेड यूनियन्स भी आती हैं। ट्रेड यूनियन कानून का दुरुपयोग कर के इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन ने जो भारत के कारखाने दारों की सब से शक्तिशाली, जमात है, उस ने अपने को इंडियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवाया। इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन—उस से शक्तिशाली जमात कोई और नहीं है, उस ने अपने को रजिस्टर्ड करवाया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) नही हो सकता।

श्री मधु लिमये : वही तो मैं कह रहा हूं। नहीं तो मैं इस सवाल को उठाता क्यों? अब कैसे उन्होंने अपने को रजिस्टर करवाया, रिश्वत दे कर किया होगा या कैसे कि होगा, मैं नहीं कह सकता। दस साल तक उस का रजिस्ट्रेशन इस कानून के तहत बम्बई में रहा। मेरे पास इंडियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट है। उस में ट्रेड यूनियन की परिभाषा की गई है—पृष्ठ 2 पर 2(एच) में है :

"Trade Union means any combination, whether temporary or permanent, formed primarily for the purpose of regulating the relations between workmen and employers or between workmen and workmen or between employers and employers or for imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business and includes any federation of two or more trade unions".

इस की कभी परिभाषा नहीं हुई और उस का फायदा उठा कर इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया जिस के फलस्वरूप दस साल तक इन के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगा। मैंने हिसाब लगाया है, इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन को इन्कमटैक्स के तहत इस तरह की छूट बिलकुल नहीं मिलनी चाहिए थी। क्या वह इंडियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट के तहत रजिस्टर हो सकते हैं या नहीं वह अलग सवाल है, उस का खुलासा संबंधित मंत्री महोदय करेंगे। लेकिन जहां तक वित्त मंत्रालय का सवाल है मेरा यह कहना है कि इन को इनकम टैक्स में छूट तो बिलकुल नहीं मिलनी चाहिये। दस साल में लगभग 90 लाख रुपये का घाटा वित्त मंत्रालय को हुआ है इनकम टैक्स को लेकर। तो मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं ...

श्री शशिभूषण (दक्षिण दिल्ली) : वह घाटा वसूल किया जाय।